जनसत्ता

20 मई, 2019

काले पर परदा

विदेशी बैंकों में भारतीयों के कालेधन को लेकर वर्षों से मामला गरमाता रहा है। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन लोग हैं जो नियम-कायदों को धता बताते हुए देश का पैसा विदेशी बैंकों में भर रहे हैं और अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने वालों के नाम कभी उजागर नहीं हो पाए। जब-जब सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी जाती है, वह गोपनीयता का हवाला देकर कोई भी जानकारी देने से मना कर देती है। हाल में सूचना के अधिकार के तहत दायर एक आवेदन में कालेधन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कालेधन के बारे में अब तक जो जानकारी स्विटजरलैंड से मिली है, उसे गोपनीयता शर्तों के कारण साझा नहीं किया जा सकता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आरटीआइ के तहत पहले भी इस तरह की अर्जियां डाली गईं, लेकिन सरकार हमेशा मना करती रही। सरकार का गोपनीयता का तर्क अपनी जगह है, लेकिन ऐसे मामलों में अगर कोई मांगी गई जानकारी नहीं मिलती तो इससे संदेह ही पैदा होता है। लगता है सरकार असलियत को छुपा रही है।

कालेधन का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। खासकर आम चुनाव आते हैं, यह मुद्दा बोतल के जिन्न की तरह बाहर निकल आता है। सारे राजनीतिक दल कालेधन के मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं, एक-दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे हैं, और हर दल यही वादा करता रहा है कि सत्ता में आते ही वह विदेश में जमा कालाधन वापस लाएगा। आम जनता के लिए कालेधन का मसला भ्रष्टाचार जितना ही महत्त्वपूर्ण है। लोगों का मानना है कि अगर भारत इन दोनों समस्याओं से पार पा जाए तो देश में खुशहाली आ सकती है। यही चुनावी घुट्टी लोगों को पिलाई जाती है। लेकिन उम्मीदें तब टूटती हैं, जब न विदेशों में कालाधन रखने वालों के नाम उजागर होते हैं न ही यह पता चलता है कि ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले आमचुनाव में लोगों को सपना दिखाया गया था कि कालाधन वापस लाया जाएगा और हरेक नागरिक के खाते में पैसे डाले जाएंगे, क्योंकि जो पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वह देश की जनता का है। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हुआ?

इसलिए अगर सरकार गोपनीयता के नाम पर कोई जानकारी नहीं देती है तो संदेह और पुख्ता होते हैं। यह संदेश जाता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम धारणा यही है कि कर चोरी के जरिए जमा बिना हिसाब-किताब वाला पैसा कालाधन है और लोग उसे ऐसे दूसरे मुल्कों में सुरक्षित रखते हैं जहां कर कानून उदार और आसान हैं। कानून की नजर में ऐसे लोग आर्थिक अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के नाम उजागर होने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कालेधन की जांच के लिए समिति भी बनाई थी, विशेष जांच दल को इसकी जांच भी सौंपी गई, कार्रवाई की दिशा में कदम भी बढ़े, लेकिन आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। यह भी हैरान करने वाली बात है कि वित्त मंत्रालय को इस बात का अनुमान ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था में और इसके बाहर कितना कालाधन चलन में है। इसलिए कालेधन की समस्या से निपटने में सरकार के प्रयास निराश करने वाले ही हैं।

बहा जात है पानी

गरमी के मौसम में देश के लगभग सभी इलाकों में जल संकट गहरा जाता है। कई जगहों पर पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हर साल इस समस्या से पार पाने के उपायों पर विचार करने का भरोसा जगाया जाता है, मगर हकीकत यही है कि स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई है। अब देश के बांधों में जल भंडारण का स्तर चिंताजनक स्तर तक नीचे आ गया है। इसके मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु सरकारों को सलाह दी है कि वे पानी का समझदारी से उपयोग करें और जब तक इन बांधों में जल भंडारण संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक केवल पेयजल के लिए इसका उपयोग किया जाए। इन राज्यों में ऐसे इक्यानबे बांध हैं, जिनके जरिए पीने के पानी और सिंचाई आदि के लिए आपूर्ति की जाती है। इन बांधों की निगरानी केंद्रीय जल आयोग करता है। देखना है, राज्य सरकारें जल आयोग की सलाह पर कितना अमल करती हैं।

बांधों में जल भंडारण पहाड़ी नदियों और बरसात के पानी से होता है। उस जल को एक तय सीमा के बाद सिंचाई, कारखानों और पेयजल के रूप में उपयोग के लिए छोड़ा जाता है। इन नदियों से इकट्ठा होने वाले पानी को लेकर राज्यों के बीच करार है। सबका हिस्सा तय है। पर जब जल संकट गहराता है, तो कई बार राज्यों के बीच तनातनी की स्थिति भी बन जाती है। समुचित पानी न मिल पाने के कारण किसान आंदोलन पर उतर आते हैं। इन सबके मद्देनजर किसी अप्रिय विवाद से बचने के लिए बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ दिया जाता है। इस तरह बांधों में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। फिर कई बार मानसून ठीक न रहने, नदियों के रास्तों में अवरोध आ जाने या बीच में ही उनका पानी रोक लिए जाने की वजह से भी बांधों के जल भंडारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर इन कारणों के अलावा सबसे गंभीर कारण है, पानी का अतार्किक उपयोग। इस मामले में समुचित नियंत्रण न होने के कारण पानी का बहुत सारा हिस्सा तय क्षेत्रों को मिलने के बजाय व्यावसायिक-व्यापारिक हितों की भेंट चढ़ जाता है।

नदियों और बांधों के जल स्तर में गिरावट की कुछ वजहें साफ हैं। छिपी बात नहीं है कि जिस तेजी से बड़े कल-कारखानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी गति से उनमें पानी की खपत भी बढ़ रही है। आज स्थिति यह है कि जो पानी शहरी आबादी को पेयजल के रूप में और किसानों को सिंचाई के लिए मिलना चाहिए, वह चीनी मिलों, शीतल पेय या शराब बनाने वाले कारखानों और बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियों को दे दिया जाता है। पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली कई नदियों में सीधे पाईप डाल कर बोतलबंद पानी के लिए जल खींच लिया जाता है। इस तरह न सिर्फ पेयजल की आपूर्ति बाधित होती है, बल्कि बांधों के जल स्तर को बनाए रखने में परेशानी पैदा होती है, क्योंकि कारोबारी लोगों का दबाव इन बांधों पर बना रहता है। गरमी में वैसे ही पानी की खपत बढ़ जाती है, पेयजल की आपूर्ति का दबाव रहता है, पर कारखानों को दिए जाने वाले पानी की मात्रा में कटौती नहीं की जाती। इसकी वजह से बांधों का जल स्तर गिरता है। इसे संतुलित किए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।

कल्पमेधा

खून की नदियां बहाने के बजाय एक आंसू पोंछने में अधिक सच्ची प्रसिद्धि है।

-बायरन

तेल संकट और भारत

जयंतीलाल भंडारी

तेल संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि सरकार एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करे। देश में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना होगा। इलेक्ट्रिक कारों पर करों की दर घटानी होगी। बड़ी संख्या में बिजली-वाहनों का उपयोग करने से प्रदूषण भी घटेगा और कार्बन उर्त्जसन में भी कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाना होगा।

इस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से खाड़ी में गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात की जल सीमा में अमेरिका के लिए कच्चा तेल ले जा रहे चार तेल टैंकरों पर हुए हमले के बाद जहां एक ओर अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर दुनियाभर में कच्चे तेल की तेजी से कीमत बढ़ने के हालात बनते जा रहे हैं। वस्तुतः वैश्विक तेल व्यापार में कोई भी रुकावट विश्व अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इससे कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा होगा। दो मई से ईरान से भारत सहित आठ देशों को कच्चा तेल आयात करने की अमेरिका की छूट खत्म हो जाने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के आसार बनते जा रहे हैं। ईरान से भारत को सस्ते पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बंद किए जाने के बाद अमेरिका से सस्ते पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सात मई को अमेरिका ने कहा कि वह भारत को सस्ते पेट्रोलियम पदार्थ नहीं दे पाएगा। ऐसे में अगले महीने से भारत के समक्ष कच्चे तेल के संकट का खतरा खड़ा हो सकता है।

अब यदि तेल उत्पादक देशों के संगठन- ओपेक और रूस जैसे देश कच्चे तेल की आपूर्ति नहीं बढ़ाते हैं, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। आर्थिक-वित्तीय शोध संगठन-ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध, ओपेक और सऊदी अरब के द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन न बढ़ाने के फैसले से इस साल के आखिर तक कच्चे तेल सौ डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। महंगे कच्चे तेल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि भारत अपनी जरूरत का करीब अस्सी फीसद कच्चा तेल आयात करता है और भारत अपनी जरूरत का दस फीसद कच्चा तेल ईरान से आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों के मामले में भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मुश्किलें भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में आ रही गिरावट से और बढ़ने वाली हैं। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का कच्चा तेल उत्पादन 4.15 फीसद घट कर 3.42 करोड़ टन रह गया, जो वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3.57 करोड़ टन था। देश में कच्चा तेल के उत्पादन में गिरावट से आयात घटाने की सरकार की योजना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2015 में एनडीए सरकार ने कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ा कर वर्ष 2022 तक कच्चे तेल के आयात में दस फीसद तक की कमी लाने की योजना बनाई थी।

यकीनन इस समय अमेरिका के आर्थिक रवैए२ ने भारत के समक्ष तेल कीमतों के तेजी से बढ़ने की बड़ी आर्थिक चिंता खड़ी कर दी है। उल्लेखनीय है कि ईरान से कच्चा तेल लेना भारत के लिए फायदेमंद होता है। ईरान भारत को साठ दिन का उधार देता है। सऊदी अरब सहित अन्य देश भारत को यह सुविधा नहीं देते हैं। ईरान तेल के बदले भारत से कई वस्तुएं भी खरीदता है। यदि ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी तो हमारे निर्यात पर भी बुरा असर पड़ेगा।

ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद होने से चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। रुपया कमजोर होगा। तेल के दाम दस फीसद बढ़े तो खुदरा महंगाई 0.24 फीसद तक बढ़ सकती है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का तेल आयात बिल एक सौ पच्चीस अरब डॉलर का था जो वर्ष 2017-18 के मुकाबले बयालीस फीसद ज्यादा था। यदि कच्चा तेल चालू वित्त वर्ष 2019-20 में महंगा हुआ तो तेल आयात बिल और बढ़ जाएगा। एक अनुमान के अनुसार यदि कच्चे तेल के भावों में एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोत्तरी होती है तो भारत को करीब 10700 करोड़ रुपए की हानि होती है, अर्थात खरीद के लिए इतनी धनराशि और देनी पड़ेगी। ऐसे में भारत को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संबंधी कठिनाई का सामना करने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा।

ऐसे में पूरी दुनिया कच्चे तेल को लेकर भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही रणनीति के तहत उपयुक्त कीमतों पर कच्चे तेल की उपलब्धता की संभावनाएं देख रही है। पिछले महीने चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर ओपेक की मनमानी पर लगाम लगाने की द्विपक्षीय भारत-चीन वार्ता को अंतिम दौर में पहुंचाया है। यह वार्ता पिछले वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल इनर्जी फोरम (आइईएफ) की सोलहवीं मंत्रीस्तरीय बैठक के बाद लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

अर्थविशेषज्ञों का मानना है कि अब चीन और भारत तेल कीमतों को लेकर अपनी नई साझेदारी के कारण कच्चे तेल के खरीदारों का एक समूह (ब्लॉक) बना सकते हैं। इससे वे तेल उत्पादक देशों से मोलभाव करके तेल की कीमत कुछ कम कराने में अवश्य सफल हो सकते हैं। चीन और भारत सबसे पहले एशियाई तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर वसूले जाने वाले एशियाई प्रीमियम को खत्म करने के लिए दबाव बना सकते हैं। एशियाई देशों के लिए तेल आपूर्ति दुबई या ओमान के कच्चे तेल बाजार से जुड़ी है। इसलिए कच्चे तेल के दाम अपेक्षाकृत अधिक वसूले जाते हैं। कच्चे तेल की खरीद में यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों की तुलना में एशियाई देशों को कुछ अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे एशियाई प्रीमियम नाम दिया गया है। एशियाई प्रीमियम अमेरिका या यूरोपीय देशों की तुलना में प्रति बैरल करीब छह डॉलर अधिक है।

चीन और भारत दुनिया में बड़े तेल आयातक देश हैं। चीन की कच्चे तेल की खपत एक करोड़ बीस लाख बैरल सालाना है और कुल वैश्विक खपत में उसकी हिस्सेदारी तेरह फीसद है। जबकि भारत की सालाना खपत चालीस लाख बैरल है जो वैश्विक खपत का करीब चार फीसद है। इस तरह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का सत्रह फीसद उपभोग करने वाले चीन और भारत नई रणनीति के जरिए तेल उत्पादक देशों से कह सकते हैं कि वे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, लिहाजा उनसे एशियाई प्रीमियम वसूल करने की बजाय उन्हें विशेष रियायत दी जानी चाहिए।

तेल संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि सरकार एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करे। देश में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना होगा। इलेक्ट्रिक कारों पर करों की दर घटानी होगी। बड़ी संख्या में बिजली-वाहनों का उपयोग करने से प्रदूषण भी घटेगा और कार्बन उर्त्जसन में भी कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाना होगा। अभी पेट्रोल और डीजल में दस फीसद एथेनॉल मिलाया जाता है। 2030 तक इसे बढ़ा कर बीस फीसद किए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास करने होंगे। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमत में चार से पांच रुपए प्रति लीटर की कमी लाई जा सकेगी।

इस समय यह भी जरूरी है कि भारत उपयुक्त दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए नए तेल बाजार खोजे। इस परिप्रेक्ष्य में रूस, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब से अधिक कच्चा तेल आयात करने के विकल्पों पर ध्यान देना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के खतरों से बचाने की होगी।

प्रतिभा की पहचान

श्रीप्रकाश शर्मा

दुनिया मेरे आगे

चीन के महान दार्शनिक और विचारक कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था- 'आप अपने लिए उस काम या नौकरी को चुनिए, जिसे आप प्यार करते हैं और तब आपको एक दिन के लिए भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी!' आशय यह है कि जब किसी नौकरी या कॅरियर का चुनाव किसी व्यक्ति के जीवन के आधे हिस्से से भी अधिक समय तक साथ चलता रहता है तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक अहम प्रश्न बार-बार उठ खड़ा होता है कि आखिर कॅरियर के चुनाव में तरजीह किसको दी जानी चाहिए- दिल को या दिमाग को! नौकरी से मिलने वाले पैसे, पद, सुविधा और पदोन्नति के आधार को या नौकरी के प्रति दिल में छिपे प्यार या आसक्ति को? अपने दिल की आवाज को अभिभावकों के दबाव को? दोराहे पर खड़ी आधुनिक युवा पीढ़ी के मुतल्लिक आज इस प्रकार के अनगिनत प्रश्नों पर गंभीर आत्मचिंतन की दरकार है।

इस हकीकत को हम आसानी से नहीं झुठला नहीं सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी नौकरी महज उसके और उसके परिवार के लिए जीविका का माध्यम नहीं होता है, बल्कि यह उस परिवार के सभी सदस्यों के जीवन, दर्शन, विचार और मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है। अपने लिए एक अच्छे कॅरियर का चुनाव महज यह निर्धारित नहीं करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए किस प्रकार के रोजगार का चुनाव करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति आने वाले वर्षों के लिए किस प्रकार के जीवन की योजना बनाता है, वह परिवार सहित अपने के लिए भी किस प्रकार की जीवन-शैली और जीवन के आदर्शों का चुनाव करता है।

गला-काट प्रतियोगिता के वर्तमान दौर में इस मामले में चुनाव के लिए विद्यार्थी अजीब संघर्ष और मानसिक तनाव की अवस्था से गुजर रहा है तो हमें इस समस्या पर बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है। बच्चों पर कॅरियर के चुनाव के लिए अभिभावकों द्वारा अपनी मर्जी थोपी जाती है तो यह और भी विकट समस्या का रूप ले लेता है और कालांतर में बेशुमार पारिवारिक-सामाजिक समस्याओं का भी सबब बन जाता है।

आज के भौतिकवादी समाज में जहां हर व्यक्ति किसी तांगे के घोड़े की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है तो ऐसे में उत्कृष्ट और मनपसंद कॅरियर चुनाव का माकूल उत्तर अपने ही प्रश्न में विलुप्त हो जाता है। अपने बच्चे को पड़ोसी के बच्चों से आगे देखने और उसे रोजगार की दुनिया में मोटी तनख्वाह की नौकरी करते देखने की चाहत में हम सबसे यह तथ्य भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी विलक्षण प्रतिभा के साथ जन्म लेता है। विश्व में करीब आठ सौ करोड़ आबादी में किसी भी दो व्यक्ति के चरित्र और गुणसूत्र आपस में नहीं मिलते। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने आप में उम्दा, असाधारण और अद्भुत है। लता मंगेश्कर जब गाती हैं तो ऐसा लगता है गोया कानों में मिसरी घोली जा रही हो। उनके परिवार वालों ने अगर उनकी अंतर्निहित प्रतिभा का पहचान किए बगैर उन्हें डॉक्टर बनने या सरकारी नौकरी करने का दबाव डाला होता तो एक करिश्माई गायन प्रतिभा की हत्या हो गई होती। रवींद्रनाथ ठाकुर को स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे प्रकृति को सबसे बड़ा शिक्षक मानते थे। वे प्रकृति को निहारते हुए विश्व के मशहूर दार्शनिक और साहित्यकार बन गए, जिनकी रचना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई। विश्व इतिहास के पन्ने ऐसे बेशुमार उदाहरणों से भरे हुए हैं जो महज इस सत्य को परिलक्षित करता है कि जीवन में सफलता की सबसे बड़ा कसौटी किसी व्यक्ति में स्वाभाविक प्रतिभा की पहचान करनी है।

लेकिन अफसोस कि इक्कीसवीं सदी में जब सूचनाओं के समंदर के रूप में इंटरनेट तक हमारी पहुंच हर दिन और आसान होती जा रही है तो हम बच्चों को मशीन सरीखा और उनमें कुदरती काबिलियत को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के रूप में तौले जाने का अपराध कर रहे हैं। यही कारण है कि किशोरों में अवसाद, मनोरोग और खुदकुशी की घटनाओं में सालों-साल इजाफा होता जा रहा है।

इस सत्य से शायद हम इनकार नहीं कर पाएं कि कॅरियर के चुनाव में पहला अधिकार विद्यार्थी का खुद का होना चाहिए। विवेकशील अभिभावक के रूप में हमें अपने संतानों को इस रूप में समझने की जरूरत है। कभी-कभी बच्चे को खुद यह पता नहीं होता है कि उनकी अपनी पहचान क्या है और उनमें कौन-सी प्रतिभा है जो उन्हें औरों से अलग और असाधारण बनाती है। यहां शिक्षक के साथ-साथ अभिभावकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कई बार हमारी सोच काफी अवैज्ञानिक और गैर-मनोवैज्ञानिक होती है।

कॉलेज और विश्वविद्यालय की फाइनल परीक्षाओं में निरंतर बढ़ती असफलता और बीच में पढ़ाई छोड़ने के आंकड़े एक बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। देश में बदतर होती जा रही बेरोजगारी की समस्या से लेकर निरंतर क्षीण होते जा रहे नैतिक मूल्य देश के भविष्य के रूप में बच्चों के दोषपूर्ण कॅरियर चुनाव का प्रतिबिंब है।

साख पर सवाल

इस बार (2019) का लोकसभा चुनाव जिन बातों के लिए जाना जाएगा, उनमें एक बात चुनाव आयोग की भूमिका पर उठते सवाल हैं। आयोग की साख में गिरावट तो दो साल पहले से ही स्पष्ट नजर अने लगी थी। लेकिन तब न मीडिया ने और न ही विपक्ष ने समय रहते इसके आलोचना की। इसलिए निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति में भी सुधार नहीं हुआ। 2017 के गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा की याद कीजिए। दोनों राज्यों के नतीजों की तिथि घोषित की गई, लेकिन चुनाव की घोषणा अलग-अलग की गई और गुजरात के चुनावों की घोषणा तब की गई जब गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री के सारे उद्घाटन और शिलान्यास कार्य पूरे हो गए थे।

लेकिन लोकसभा के चुनाव की घोषणा के समय से ही निर्वाचन आयोग का आचरण सत्तारूढ़ दल की ओर झुकाव का रहा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष दिखने के लिए प्रधानमंत्री की बायोपिक के प्रदर्शन पर तो रोक लगाई, लेकिन नमो टीवी नामक मीडिया चैनल पर रोक नहीं लगाई। दूसरे नेताओं के अपशब्दों के लिए तो उन्हें दंडित किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के दुर्वचनों की कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया गया। अंत में सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद एक-एक करके शिकायतों का निपटारा किया गया और बाद में सब में उन्हें क्लीन चिट दी गई। हार्दिक पटेल का नामांकन रद्द करना और प्रज्ञा ठाकुर का स्वीकार करना और वाराणसी में तेज बहादुर यादव सहित कई नामांकनों को बहुत मामूली गलतियों के लिए अस्वीकार करना भी चर्चा में रहा।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयुक्त को एक बार नियुक्त करके उसको उसके पद से आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अब समय आ गया है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए।

● *आनंद मालवीय, इलाहाबाद*

कठोर कार्रवाई की जरूरत

आए दिन यौन शोषण, अमर्यादित व्यवहार और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज होते हैं। इनमें तीस से पैंतीस फीसद मामले फर्जी होते हैं, जो कि शिकायतकर्ता अपने निजी स्वार्थ के लिए लगाते हैं। हाल में एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया था। मामले की जांच की गई, जिसमें मामला झूठा पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश को क्लीन चिट दे दी।

लेकिन अब सवाल यह है कि क्या झूठा आरोप लगने वाला अपराधी नहीं है? देश में झूठ बोल कर पुरुषों को फंसाने का अधिकार महिलाओं को है और यदि वह फर्जी हो तो उसे दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को क्यों नहीं है? अगर इसी तरह लोगों को झूठ का फायदा मिलता रहा और मामला झूठा होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो लोगों का सच और न्यायपालिका दोनों से विश्वास उठ जाएगा। अतः न्यायपालिका को झूठे मामले दर्ज कराने वालों को कठोर दंड देना चाहिए, ताकि कोई भी फर्जी मामला दर्ज करने से पहले कई बार सोचे।

● *शिवेंद्र सिंह, नोएडा*

मुजफ्फरपुर कांड पर चुप्पी

बिहार के मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह की चौंतीस बच्चियों से दुष्कर्म और ग्यारह बच्चियों की हत्या झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन इस घटना से सत्ता पक्ष असहज नहीं हुआ, बल्कि जब तक इस कांड से पर्दा नहीं उठा तब तक इसके आरोपित ब्रजेश ठाकुर पर सरकार मेहरबान रही। उसके अखबार 'प्रातःकमल' को करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते रहे। मुजफ्फरपुर में ठाकुर का आवास सफेदपोशों का अतिथिशाला था। बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री के पति सहित अनेक राजनेताओं के इस कांड में शामिल होने की बात कही सामने आई है। चुनाव प्रचार के दौरान मुजफ्फरपुर में बड़े-बड़े राजनेताओं की सभा हुई, लेकिन इस कांड का जिक्र तक नहीं हुआ। मानो कुछ हुआ ही नहीं या ये सब घटनाएं होती रहेंगी। किसी की अंतरात्मा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बिहार की अंतरात्मा डोल गई। भले ही कोई सुशासन का दंभ भरे, लेकिन राजसत्ता के चेहरे पर कलंक की टीका लग गया। राजनेताओं पर से विश्वास उठ गया। अगर इस कलंक को धोना है और बिहार की उन बेटियों के कोई न्याय के पक्षधर हैं तो वे न्यायलय को जांच में सहयोग करें। इतने बड़े कांड की जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है, न सरकार इस पर अपना मुंह खोलती है।

● *प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना*

छवि और विवाद

विश्व प्रसिद्ध पत्रिका 'टाइम' ने अपने हालिया संस्करण में 'इंडियाज डिवाइडर इन चीफ' शीर्षक से एक आवरण कथा छापी है जिसमे प्रधानमंत्री को भारत का विभाजक बताया गया है। 'टाइम' का यह शीर्षक और रिपोर्ट विवादों में घिर गई है। जहां एक ओर भाजपा इसे सिरे से खारिज कर रही है, वहीं अन्य दल इसे आड़े हाथों लेकर प्रधानमंत्री की असलियत बता रहे हैं। सवाल है कि क्या यह तथ्यात्मक रूप से सही है..?

इस लेख को लिखने वाले आतिश तासीर ने यह किस आधार पर कहा है? क्या प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं का वितरण जातिगत आधार पर किया है या फिर आए दिन सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं? क्या एक विशेष समुदाय देश छोड़ कर पलायन कर रहा है या फिर मस्जिदों और चर्चों पर हमले हो रहेहैं? अगर नहीं तो यह लेख और लेखक किस विभाजन की बात कर रहा है! रही बात कथित गो-रक्षकों की तो सनद रहे प्रधानमंत्री ने अपने मंच से ऐसे फर्जी लोगों को कड़ी हिदायत देते हुए चेताया भी है। सवाल यह है कि क्या ऐसी मशहूर पत्रिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पांच सालों को एक विवादित शीर्षक में कैद करना चाहिए जिसका कोई मजबूत आधार न हो? हाल ही में दो बड़े राष्ट्रों रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया ने 'सिओल पीस प्राइज' और संयुक्त राष्ट्र ने 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' सम्मान प्रधानमंत्री को दिया था। तो क्या शांति पुरस्कार अशांति और सर्वोच्च सम्मान बंटवारे के लिए मिलता है..?

● *संजय दुबे, नई दिल्ली*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com